



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

No. 293]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2008/ज्येष्ठ 7, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2008/JYAISTHA 7, 1930

गृह मंत्रालय

(सी एस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2008

सा.का.नि. 406(अ).—बंदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध फ्रांस गणराज्य पर लागू होंगे तथा भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच हुए करार के पाठ को निम्न प्रकार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी देश कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से;

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य कोई अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दंडित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सजा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :

अनुच्छेद 1

परिभाषा

इस करार के प्रयोजन के लिए :

(क) “निर्णय” से तात्पर्य किसी ऐसे न्यायिक निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;

- (ख) "दण्ड" से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा अपने आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आदेशित किसी सीमित या असीमित समयावधि के लिए आजादी से वंचित रखे जाने का उपाय या कोई दंड है। वर्तमान करार के कार्यान्वयन के लिए अभिव्यक्ति "दंड" में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के अंतिम निर्णय या आदेश भी शामिल होंगे जिन्हें बाद में अन्तरणकर्ता देश द्वारा राज्य क्षमा या माफी द्वारा किसी निश्चित या अनिश्चित समयावधि के लिए आजादी से वंचित करने में परिणत कर दिया गया हो;
- (ग) "दंडित व्यक्ति" से तात्पर्य किसी फौजदारी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के तहत कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति से है;
- (घ) "प्राप्तकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसको दंडित व्यक्ति को सजा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जाएगा अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ङ) "अंतरणकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जाएगा या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

## अनुच्छेद 2

### सामान्य सिद्धांत

1. इस करार के प्रावधानों के अनुसार एक संविदाकार देश के भूभाग में दंडित व्यक्ति को सजा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भूभाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सजा काट सके। इस संबंध में दंडित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत अन्तरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
2. इस अन्तरण का अनुरोध अन्तरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश द्वारा किया जाएगा। अन्तरण का सरकारी अनुरोध, अनुरोधकर्ता देश द्वारा अनुरोध प्राप्तकर्ता देश को भेजा जाता है। यदि दंडित व्यक्ति अपनी इच्छा अन्तरणकर्ता देश को भेजता है और यदि उस देश में इसकी कोई निर्धारित प्रक्रिया है तो आवेदनपत्र उस प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। उक्त आवेदनपत्र अन्तरणकर्ता देश में प्रचलित विधि के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, जो उसकी ओर से कार्य करने का हकदार है, द्वारा भी दिया जा सकता है।

## अनुच्छेद 3

### अन्तरण की शर्तें

1. इस करार के अन्तर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अन्तरित किया जा सकता है:

- (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
- (ख) निर्णय अंतिम है और अंतरणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच, विचारण अथवा अन्य आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है;
- (ग) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय भोगी जाने वाली शेष सजा की अवधि कम से कम छः माह बची हो;
- (घ) प्रवर्तनयोग्य दंड में स्वतंत्रता की वचना शामिल है, मृत्युदंड नहीं;
- (ङ) कि व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिस कृत्य अथवा गलती के लिए दंड दिया गया था, वह प्राप्तकर्ता देश में अपराध के रूप में दंडनीय हो अथवा यदि उस देश के भूभाग में वे कृत्य किए जाते तो वे अपराध माने जाते;
- (च) प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (छ) अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसरण में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति; और
- (ज) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो।

2. आपवादिक मामलों में, यदि दंडित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

#### अनुच्छेद 4

#### सूचना भेजने का दायित्व

1. कोई भी दंडित व्यक्ति, जिस पर यह करार लागू हो, को इस करार का सारांश अंतरणकर्ता देश द्वारा बताया जाएगा।
2. इस करार के तहत अनुरोध पर निर्णय लिए जाने के उद्देश्य से अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज भेजेगा :-

- (क) दंडित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
- (ग) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;

- (घ) दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
  - (ङ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया;
  - (च) जब कभी उपयुक्त हो, दंडित व्यक्ति की कोई भी डाक्टरी अथवा सामाजिक रिपोर्ट, अंतरणकर्ता देश में उसके इलाज के बारे में सूचना और प्राप्तकर्ता देश में उसके आगे के उपचार के लिए कोई सिफारिश;
  - (छ) कोई अन्य जानकारी जिसके लिए प्राप्तकर्ता देश यह विनिर्दिष्ट करे कि यह संबंधित मामले में अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;
  - (ज) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति, अथवा जहां उसकी आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए की गई घोषणा, जिस पर कोई भी संविदाकार देश आवश्यक समझे, उसकी सहमति का सत्यापन करते हुए, अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसरण में उसकी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति का अनुरोध;
  - (झ) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो चुका है।
3. इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज तभी भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है :
- (क) एक विवरण या दस्तावेज जिसमें यह उल्लेख हो कि दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक है;
  - (ख) प्राप्तकर्ता देश के उस प्रासंगिक कानून की प्रति जिसमें यह विहित हो कि अंतरणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति को जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए दंडित किया गया था वे प्राप्तकर्ता देश में फौजदारी अपराध के रूप में दंडनीय हैं अथवा यदि ये कृत्य अथवा चूकें उसके भू-भाग में की गई हों तो यह एक फौजदारी अपराध होगा;
  - (ग) दंडित व्यक्ति के अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में दंड की अवधि और प्रवर्तन से संबंधित किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण और साथ में यदि लागू हो तो, उसके अंतरण पर इस करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण;
  - (घ) दंडित व्यक्ति का अंतरण स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की स्वीकृति संबंधी वक्तव्य और दंडित व्यक्ति के शेष बचे दंड का, इस करार के प्रावधानों के अध्याधीन प्रबंध करना;
  - (ङ.) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश जरूरी समझे।

**अनुच्छेद 5****अनुरोध एवं उत्तर**

1. अंतरण संबंधी अनुरोध लिखित में किए जाएंगे तथा ये राजनयिक चैनलों के माध्यम से अनुरोधकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से अनुरोध प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण को सम्बोधित होंगे। इन अनुरोधों के उत्तर इन्हीं चैनलों के माध्यम से दिए जाएंगे।
2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रयोजनार्थ भारत के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकारी, गृह मंत्रालय होगा और फ्रांस के संबंध में न्याय मंत्रालय।
3. अनुरोध प्राप्तकर्ता देश अनुरोधकर्ता देश को तत्काल अपने इस निर्णय से अवगत कराएगा कि वह इस अंतरण के अनुरोध से सहमत है अथवा नहीं।

**अनुच्छेद 6****सहमति तथा उसका सत्यापन**

1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 (छ) के अनुसरण में अंतरण की सहमति देने वाला व्यक्ति ऐसी सहमति स्वेच्छापूर्वक और उसके विधिक परिणामों की पूरी जानकारी के साथ दे रहा है। ऐसी सहमति देने की प्रक्रिया अंतरणकर्ता देश के कानून से अधिशासित होगी।
2. अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने का अवसर देगा कि सहमति इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई है।

**अनुच्छेद 7****प्राप्तकर्ता देश पर अंतरण का प्रभाव**

1. प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 8 में दी गई शर्तों के तहत किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के जरिए, जैसा भी उसके राष्ट्रीय कानून के तहत अपेक्षित हो, दंड का प्रवर्तन जारी रखेगा।
2. इस करार के अनुच्छेद 10 तथा 11 के उपबंधों के अधधीन दंड का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा नियंत्रित होगा और केवल वही देश सभी उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

2023/10/8-2

## अनुच्छेद 8

### दंड का निरंतर प्रवर्तन

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश में यथा निर्धारित दंड की कानूनी प्रकृति एवं अवधि के प्रति बाध्य होगा।
2. तथापि, यदि दिया गया दंड अपने स्वरूप अथवा अवधि की दृष्टि से प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हो अथवा उसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो तो वह देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा दंड को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित सजा अथवा उपाय में परिवर्तित कर सकता है। जहां तक इसके स्वरूप तथा अवधि का संबंध है, सजा अथवा उपाय यथासंभव अंतरणकर्ता देश के फैसले में दी गई सजा के संगत होने चाहिए। तथापि, इससे अंतरणकर्ता देश में दी गई सजा के स्वरूप अथवा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुच्छेद 9

### अंतरणकर्ता देश पर दंड पूरा होने का प्रभाव

जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दंड पूरा हो गया है तो वह दंड अंतरणकर्ता देश में प्रवर्तनीय नहीं रहेगा।

## अनुच्छेद 10

### निर्णय की पुनरीक्षा

केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।

## अनुच्छेद 11

### माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण

कोई भी संविदाकारी देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दंड का लघुकरण कर सकेगा।

## अनुच्छेद 12

### दंड के प्रवर्तन की समाप्ति

जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

## अनुच्छेद 13

### दंड के प्रवर्तन संबंधी सूचना

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा:

- (क) जब दंड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा
- (ख) यदि दंड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश को चाहिए कि वह दंडित व्यक्ति की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास करे ताकि वह कारागार से भागने पर प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत हुए दंडनीय अपराध के अतिरिक्त स्वयं को मिले दण्ड का शेष भाग पूरा कर सके।

2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

## अनुच्छेद 14

### अभिवहन

1. यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा।
2. ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को ऐसे अभिवहन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा। इस अधिसूचना में निम्नलिखित पैराग्राफों के आवेदन को अनुमति प्रदान करने संबंधी सूचना सहित अन्य आवश्यक सूचना की जानकारी होगी।
3. वह देश, जिसके भू भाग पर अंतरण किया जाना है, दंडित व्यक्ति के अभिवहन से मना कर सकता है अगर दंडित व्यक्ति उसके राष्ट्रियों में से एक हो अथवा जिस अपराध के लिए उसे दण्ड दिया गया हो, वह अपराध, उसके स्वयं के कानून के अंतर्गत अपराध न हो;

4. वह देश जिसे अभिवहन हेतु अनुरोध किया गया है वह दंडित व्यक्ति को उस अवधि तक हिरासत में रख सकता है जो कि इसके भू-भाग में अभिवहन के लिए अति आवश्यक है।

5. यदि किसी देश के भू-भाग के ऊपर हवाई मार्ग का उपयोग उसके भू-भाग में उतरे बिना किया जा रहा हो तो अभिवहन के लिए किसी अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, अभिवहन करने वाला देश उस देश को सूचित करेगा जिसके भू-भाग में उड़ान भरी जानी हो।

### अनुच्छेद 15

#### लागत

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश अंतरण में होने वाले व्यय की सम्पूर्ण अथवा आंशिक वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य साधन से कर सकता है।

### अनुच्छेद 16

#### भाषा

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध प्राप्तकर्ता देश की भाषा अथवा किसी एक राजभाषा में अनूदित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

### अनुच्छेद 17

#### टैम्पोरल आवेदन

यह करार इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दंड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

### अनुच्छेद 18

#### अंतिम प्रावधान

1. यह करार, अनुसमर्थन के अध्वधीन होगा। प्रत्येक संविदाकारी देश इस करार के लागू होने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं के पूर्ण होते ही, शीघ्रातिशीघ्र, कूटनीतिक माध्यमों से दूसरे को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा।



यह करार दूसरी अधिसूचना की तारीख के बाद दूसरे महीने की पहली तारीख से लागू होगा।

2. यह करार उस तारीख से छः माह तक लागू रहेगा जिस तारीख को कोई भी संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को इसे समाप्त करने के बारे में लिखित सूचना देगा।

3. किसी भी परिसमापन के बावजूद यह करार उस दंडित व्यक्ति के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिसे इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस करार के साक्ष्य के रूप में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके सभी तीनों पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे नई दिल्ली में दिनांक 25 जनवरी, 2008 को हिन्दी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा की दो प्रतियों में तैयार किया गया है।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

फ्रांस गणराज्य की  
सरकार की ओर से

[फा. सं. V-17011/10/2004-पी आर]

निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(C S Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2008

**G.S.R. 406(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Republic of France and notifies the text of the agreement entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of France as follows, namely :—

Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of France on the Transfer of Sentenced Person.

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of France hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own society;

Have agreed as follows:

2023/12/18-3

## ARTICLE 1

### Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (a) "judgment" means a judicial decision or order imposing a sentence.
- (b) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a limited or unlimited period of time in the exercise of its criminal jurisdiction. For the implementation of the present Agreement, the expression "sentence" shall also cover final judicial decisions or orders of a court or a tribunal imposing capital punishment which have been subsequently commuted in the transferring State by amnesty or pardon into a sentence involving deprivation of liberty for a limited or unlimited period of time;
- (c) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under a decision or order passed by a criminal court or tribunal;
- (d) "receiving State" means the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
- (e) "transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

## ARTICLE 2

### General Principles

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him or

her. To that end, the sentenced person may express to the transferring State or the receiving State his or her willingness to be transferred under this Agreement.

2. Transfer may be requested either by the transferring State or the receiving State. The official request for transfer is sent to the requested State by the requesting State. If the sentenced person expresses his or her willingness to be transferred to the transferring State and if that State has a prescribed procedure, the application will be made according to the said procedure. The said application may also be made by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State.

### ARTICLE 3

#### Conditions for transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:

- (a) the person is a national of the receiving State;
- (b) the judgment is final and no inquiry, trial or other criminal proceedings are pending against the sentenced person in the transferring State;
- (c) at the time of receipt of the request for transfer, the remainder of the sentence to be served is at least six months.
- (d) the enforceable sentence involves deprivation of liberty and not death penalty.
- (e) that the acts or omissions for which that person was sentenced are those which are punishable as a criminal offence in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory.
- (f) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;
- (g) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his or her age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his or her behalf in accordance with the law of the Transferring State; and
- (h) the transferring and receiving States agree to the transfer.

2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

### ARTICLE 4

#### Obligation to furnish information

1. Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the transferring State of the substance of this Agreement.

2. For the purpose of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State:

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person;
- (b) his or her address, if any, in the receiving State;
- (c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (e) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (f) whenever appropriate, any medical or social report of the sentenced person, information about his or her treatment in the transferring State, and any recommendation for his or her further treatment in the receiving State;
- (g) any other information which the receiving state may specify as being necessary in a given case to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him or her under its law.
- (h) the request of the sentenced person to be transferred or a declaration from him or her or, where in view of his or her age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, any other person entitled to act on his or her behalf in accordance with the law of the transferring State, attesting his or her consent, and
- (i) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.

3. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;

- (b) a copy of the relevant law of the receiving state establishing that the acts or omissions for which the sentenced person was sentenced in the transferring state are punishable as a criminal offence in the receiving state, or would constitute a criminal offence if committed on its territory.
- (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 8 of this Agreement on his or her transfer;
- (d) the statement of the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person under the provisions of this Agreement;
- (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

## ARTICLE 5

### Requests and replies

1. Requests for transfer shall be made in writing and addressed through the central authority of the requesting State through diplomatic channels to the central authority of the requested State. Replies shall be communicated through the same channels.
2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the central authority shall be, in relation to India, the Ministry of Home Affairs; and in relation to the France, the Ministry of Justice.
3. The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

## ARTICLE 6

### Consent and its verification

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(g) of Article 3 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.

2023 4 Dec-4

2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

## ARTICLE 7

### Effect of transfer for the receiving State

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 8 of this Agreement.

2. Subject to the provisions of Article 10 and 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

## ARTICLE 8

### Continued enforcement of sentence

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined in the transferring State.

2. If, however, the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the receiving State, or its law so requires, that State may, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.

## ARTICLE 9

### Effect of completion of sentence for the transferring State

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, the sentence shall cease to be enforceable in the transferring State.

**ARTICLE 10****Review of Judgment**

The transferring State alone shall decide on any application for review of the judgment.

**ARTICLE 11****Pardon, amnesty or commutation**

Either of the contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

**ARTICLE 12****Termination of enforcement of sentence**

The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

**ARTICLE 13****Information on enforcement of sentence**

1. The receiving State shall notify the transferring State:
  - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
  - (b) If the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the receiving State shall make every effort to have the sentenced person arrested so that he or she serves the remainder of his or her sentence, in addition to the criminal offence committed under the relevant law of the receiving State on escape from prison.
2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

20234708-5

## ARTICLE 14

### Transit

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such an arrangement.
2. The State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other State. This notification shall convey any necessary information, including information allowing the application of the following paragraph.
3. The State over whose territory the transfer is to be made may refuse to grant transit if the sentenced person is one of its nationals or if the offence for which the sentence was imposed is not an offence under its own law;
4. The State requested to grant transit may hold the sentenced person in custody for the period of time that is strictly necessary for the transit on its territory;
5. No request for transit is required where air transportation is being utilized over the territory of a State and if no landing is scheduled. However, the State which makes the transit shall inform the State over whose territory the flight is to be made.

## ARTICLE 15

### Costs

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.



**ARTICLE 16****Language**

Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the language or one of the official languages of the requested State.

**ARTICLE 17****Temporal Application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

**ARTICLE 18****Final provisions**

1. This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its constitutional procedures required to allow this Agreement to come into force.

This Agreement shall come into force on the first day of the second month following the date of the second notification.

2. The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons who have been

transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

**In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.**

**Done in duplicate at New Delhi on the 25th day of January 2008, in Hindi, English and French languages, the three texts being equally authentic.**

**For the Government of  
the Republic of India :**

**For the Government of the  
Republic of France :**

[F. No. V-17011/10/2004-PR]

NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.